आईएमएफ कोटा

संदर्भ

वित्त मंत्री ने नवनियुक्त आईएमएफ की मौद्रिक और वित्तीय समिति के अध्यक्ष के साथ एक आभासी बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कोटा की सामान्य समीक्षा को समय पर पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

पृष्ठभूमि

- अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के प्रस्ताव के अनुसार, कोटा की 16वीं सामान्य समीक्षा 15 दिसंबर, 2023 तक पूरी हो जानी चाहिए।
- भारत हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

आईएमएफ कोटा क्या है

- आईएमएफ एक कोटा आधारित संस्था है।
- कोटा आईएमएफ की वित्तीय और शासन संरचना के निर्धारक हैं।
- किसी सदस्य देश का कोटा मोटे तौर पर विश्व अर्थव्यवस्था में इसकी सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है।
- कोटा विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर), आईएमएफ के खाते की इकाई में अंकित हैं।
- मौजूदा फॉर्मूले पर 2008 में सहमति बनी थी।

$$(0.50 * GDP + 0.30 * Openness + 0.15 * Variability + 0.05 * Reserves)^{\text{compression factor}}$$

सामान्य कोटा समीक्षा

- आईएमएफ का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नियमित अंतरालों पर कोटा की सामान्य समीक्षा करता है (अधिक से अधिक 05 वर्ष अलग नहीं)।
- सामान्य समीक्षा सदस्यों के कोटा शेयरों में विश्व अर्थव्यवस्था में उनकी सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए पुनर्संरेखण की अनुमति देती है।
- इसके अतिरिक्त, कोई सदस्य सामान्य समीक्षा के बाहर किसी भी समय तदर्थ कोटा समायोजन का अनुरोध कर सकता है।
- कोटा में किसी भी परिवर्तन को कुल मतदान शक्ति के 85% बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, और किसी सदस्य का अपना कोटा उसकी सहमति के बिना नहीं बदला जा सकता है।
- कोटा की सामान्य समीक्षा में संबोधित किए गए दो मुख्य मुद्दे हैं (i) समग्र कोटा वृद्धि का आकार और (ii) सदस्यों के बीच वृद्धि का वितरण।

आईईपीएफए

सन्दर्भ

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईईपीएफए) और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) ने आईईपीएफए के छठे स्थापना दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।

आईईपीएफए के बारे में

- निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के प्रशासन के लिए, भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के प्रावधानों के तहत 2016 में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की स्थापना की।
- प्राधिकरण को निवेशकों को शेयरों, दावा न किए गए लाभांश, परिपक्व जमा/डिबेंचर आदि की वापसी करने और निवेशकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
- सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है।

आईईपीएफ के बारे में

- निवेशकों की जागरूकता को बढ़ावा देने और निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205C के तहत IEPF की स्थापना की गई है।
- निम्नलिखित राशियां जो भुगतान के लिए देय होने की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए अवैतनिक और लावारिस बनी रहीं, उन्हें फंड में जमा किया जाता है:

i. कंपनियों के अवैतनिक लाभांश खातों में राशि।
ii. किसी भी प्रतिभूतियों के आवंटन के लिए और वापसी के लिए कंपनियों द्वारा प्राप्त आवेदन राशि।
iii. कंपनियों के साथ परिपक्व जमा।
iv. कंपनियों के साथ परिपक्व डिबेंचर।
v. खंड (i) से (iv) में संदर्भित राशियों पर अर्जित ब्याज।
vi. निधि के प्रयोजनों के लिए केंद्र या राज्य सरकारों, कंपनियों या किसी अन्य संस्थान द्वारा निधि को दिए गए अनुदान और दान;
vii. फंड से किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज या अन्य आय।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण
INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND AUTHORITY
(कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry Of Corporate Affairs, Government Of India)
IEPF

AWaRe (एक्सेस, वॉच, रिजर्व)

संदर्भ

लैंसेट में प्रकाशित एक नए अध्ययन में भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के बारे में महत्वपूर्ण खुलासे किए गए हैं।

मुख्य विचार

• 2019 में भारत में उपयोग किए जाने वाले आधे से अधिक एंटीबायोटिक फॉर्मूलेशन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में सूचीबद्ध नहीं थे।
• एज़िथ्रोमाइसिन और सेफिक्साइम-ओफ़्लॉक्सासिन भारत में सबसे पहले और दूसरे सबसे अधिक खपत वाले एंटीबायोटिक थे।
• एज़िथ्रोमाइसिन सबसे अधिक खपत वाला 'वॉच' एंटीबायोटिक था।
• सेफिक्साइम-ओफ़्लॉक्सासिन सबसे अधिक हतोत्साहित करने वाला फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन (FDC) था और आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) के बाहर सबसे अधिक खपत वाला फॉर्मूलेशन भी था।
• विश्व स्तर पर पूर्ण मात्रा में सबसे बड़ा एंटीबायोटिक उपभोक्ता होने के बावजूद भारत में एंटीबायोटिक उपयोग निगरानी की औपचारिक प्रणाली का अभाव है।
• 2019 में खपत किए गए 5,071 मिलियन डीडीडी में से, 'वॉच' श्रेणी के अंतर्गत आने वाले एंटीबायोटिक्स ने 54.9% (2,783 मिलियन) डीडीडी का योगदान दिया। • • वैश्विक लक्ष्य 'एक्सेस' एंटीबायोटिक्स के लिए कम से कम 60% हिस्सा होना है, और भारत में अनुपात लगभग उल्टा है।

AWaRe के बारे में

• AWaRe उपयुक्त एंटीबायोटिक उपयोग को मापने और सुधारने के लिए WHO द्वारा समर्थित एक प्रबंधन ढांचा है।
• यह एंटीबायोटिक दवाओं को एक्सेस, वॉच और रिजर्व समूहों में वर्गीकृत करता है।
• एक्सेस - इसमें आमतौर पर उपचार की पहली या दूसरी पंक्ति के रूप में उपयोग किए जाने वाले एंटीबायोटिक्स शामिल हैं।
• वॉच - इसमें व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शामिल हैं जिनमें प्रतिरोध की उच्च संभावना है और इसका उपयोग केवल विशिष्ट संकेतों के लिए किया जाना चाहिए।
• रिजर्व - अंतिम उपचार एंटीबायोटिक्स।

डीडीडी (परिभाषित दैनिक खुराक)
• यह एंटीबायोटिक उपयोग का विश्व स्तर पर स्वीकृत मानक उपाय है।
• वयस्कों में इसके मुख्य संकेत के लिए इसे दवा की प्रति दिन औसत रखरखाव खुराक के रूप में परिभाषित किया गया है।
• यह उपाय कीमत, मुद्राओं, पैकेज के आकार और ताकत से स्वतंत्र है जो जनसंख्या समूहों और समय में नशीली दवाओं के उपयोग के अध्ययन में मदद करता है।

परियोजना प्रबंधन इकाई

सन्दर्भ

केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में नई दिल्ली में कृषि में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• कृषि निवेश और कृषि में सकल पूंजी निर्माण में वृद्धि कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण की कुंजी है।
• निजी क्षेत्र के निवेश के साथ-साथ कृषि में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न पहलों के रूप में सार्वजनिक निवेश का संयोजन कृषि क्षेत्र के लिए एक बल गुणक हो सकता है।
• सरकार पैदावार में सुधार, घाटे को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में पीपीपी पहलों को प्रोत्साहित करने की इच्छुक है।
• पीपीपी पहलों से कृषि में निजी पूंजी का निवेश होगा , सरकारी निवेश पर दबाव काम होगा और इस क्षेत्र में गतिशील और मूल्य वर्धित विकास की साझा दृष्टि में केंद्र और राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र और किसानों को संरेखित करेगा।
• पीपीपी पहलों से किसानों को लाभ पहुंचाने और उनके प्रभाव में सुधार लाने के लिए विभिन्न योजनाओं का अभिसरण भी होगा।
• इस पीपीपी पहल का प्राथमिक उद्देश्य अतिरिक्त मूल्य सृजित करके छोटे किसानों की आय में वृद्धि करना है, -s

गुणवत्ता इनपुट के प्रावधान से,
बाजार से जुड़ाव और मूल्यवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विस्तार।
पीपीपी पहलों से कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण, जलवायु अनुकूल फसलों में अनुसंधान को बढ़ावा देना,
कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना,
कृषि निर्यात में वृद्धि।

• विशेष उद्देश्य राज्यों को उनके संबंधित कृषि-जलवायु क्षेत्रों की पूरी क्षमता को अनलॉक करने और कृषि-उत्पादों की विस्तृत विविधता और उत्पादकों को घरेलू और निर्यात बाजारों के साथ बेहतर ढंग से एकीकृत करने में मदद करना है।
• पीपीपी मॉडल: सार्वजनिक-निजी भागीदारी में एक सरकारी एजेंसी और एक निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच सहयोग शामिल होता है जिसका उपयोग सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क, पार्क और कन्वेंशन सेंटर जैसी परियोजनाओं के वित्तपोषण, निर्माण और संचालन के लिए किया जा सकता है।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से किसी परियोजना को वित्तपोषित करने से किसी परियोजना को जल्दी पूरा किया जा सकता है ।

एनसीईआरटी रिपोर्ट

संदर्भ

हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) द्वारा "रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और न्यूमेरिकेसी 2022 के साथ ओरल रीडिंग फ्लुएंसी" के लिए बेंचमार्किंग पर एक अध्ययन किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- तमिल में पढ़ने वाले बयालीस प्रतिशत बच्चों में बुनियादी पठन कौशल का अभाव है। तमिलनाडु में बुनियादी संख्यात्मक कौशल की कमी वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद जम्मू और कश्मीर, असम और गुजरात का स्थान है।
- कक्षा 3 के कम से कम 37 प्रतिशत छात्र उस श्रेणी में हैं जिनका कहना है कि "शिक्षार्थियों के पास सीमित ज्ञान और कौशल है और वे बुनियादी ग्रेड-स्तरीय कार्यों को आंशिक रूप से पूरा कर सकते हैं।
- स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के बच्चे हैं जिनके पास या तो पर्याप्त ज्ञान और कौशल है, या जिन्होंने बेहतर ज्ञान और कौशल विकसित किया है और जटिल ग्रेड-स्तरीय कार्यों को पूरा कर सकते हैं।

- खासी, बंगाली, मिजो, पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने वाले बच्चों ने मौखिक पठन दक्षता के उच्चतम स्तर का प्रदर्शन किया।
- रिपोर्ट का उद्देश्य कक्षा 3 के छात्रों के बारे में विश्वसनीय और वैध डेटा प्रदान करना था ताकि यह पता चल सके कि वे आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में क्या करने में सक्षम हैं और सीखने के परिणाम प्राप्त किए जा रहे हैं।
- निपुण : शिक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2021 में राष्ट्रीय मिशन के रूप में समझ और संख्यात्मकता (NIPUN) के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल शुरू की, ताकि कक्षा 3 के अंत में सभी बच्चों को वर्ष 2026-2027 तक मूलभूत कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020 22

सन्दर्भ

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा सामाजिक सुरक्षा पर नवीनतम रिपोर्ट (वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22: एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय सहयोगी रिपोर्ट) के अनुसार, केवल 24.4% भारतीय, यहां तक कि बांग्लादेश से भी कम (28.4%) , किसी भी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत हैं।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट ILO की 'वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2021-22' की सहयोगी है, जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्रीय अवलोकन देती है।
- इसके अनुसार मंगोलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में 100% सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क है, जबकि म्यांमार और कंबोडिया में यह संख्या 10% से कम है।
- रिपोर्ट के अनुसार, एशिया प्रशांत क्षेत्र में चार में से तीन कामगार काम के दौरान बीमारी या चोट लगने की स्थिति में सुरक्षित नहीं हैं।

भारत के बारे में

- कवरेज में असमानता: अंशदायी योजनाओं के साथ आम तौर पर औपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों और गैर-अंशदायी योजनाओं में काम करने वालों तक सीमित होने के कारण, भारत के सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के 5% (2,277) से कम हैं।
- हाल की पहल: रिपोर्ट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) जैसे सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न स्तरों को मिलाकर कवरेज के अपने प्रगतिशील विस्तार के माध्यम से अंशदायी और गैर-अंशदायी योजनाओं के संयोजन के माध्यम से प्राप्त भारत की उच्च कवरेज दर की सराहना की, जो अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 100 दिनों तक की सुरक्षा प्रदान करता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण खबरें

यूएस स्टार्ट-अप सेतु

सन्दर्भ

वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने हाल ही में अपनी यूएसए यात्रा के दौरान सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी क्षेत्र में यूएस स्टार्टअप सेतु कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- यह पहल भारत में स्टार्ट-अप को यूएस-आधारित निवेशकों और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के नेताओं को वित्त पोषण, बाजार पहुंच और व्यावसायीकरण में परामर्श और सहायता के लिए जोड़ेगी।
- स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विकसित मेंटरशिप पोर्टल के माध्यम से बातचीत का समर्थन किया जाएगा, जिसे MAARG (मेंटरशिप,, एडवाइजरी,

MAARG के बारे में

• यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा विकसित भारत में स्टार्टअप के लिए एकल-स्टॉप समाधान खोजक है।
• पोर्टल को इस विचार के साथ विकसित किया गया है कि देश के हर कोने से एक संरक्षक से जुड़ने के लिए पहुंच योग्य हो।
• एक मेंटर स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन करने में मानवीय बुद्धिमत्ता की पेशकश करेगा। अब तक, दुनिया भर में 200 से अधिक सलाहकारों को MAARG पर सफलतापूर्वक शामिल किया गया है।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस – SURVEI

सन्दर्भ

रक्षा मंत्रालय के उत्कृष्टता केंद्र - उपग्रह और मानव रहित रिमोट व्हीकल इनिशिएटिव (सीओई - सर्वेक्षण) ने मसौदा अवधारणा पत्र प्रकाशित किया है, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियों का अनुरोध किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• कागजी उद्देश्य भूमि सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए ड्रोन छवियों के उत्पादन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक समान मानक निर्धारित करना है।

• मानकों को अंतिम रूप देने के परिणामस्वरूप ड्रोन का उपयोग करके भूमि सर्वेक्षण पर दुनिया का पहला मानक स्थापित किया जा सकता है।

इंडिया आइडियाज समिट

सन्दर्भ

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, दक्षिण एशिया द्वारा आयोजित इंडिया आइडियाज समिट में भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

• आयोजन का विषय "अमेरिका-भारत समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिकतम करना।

• मंत्री ने संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करने और अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों देशों में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच अधिक से अधिक शैक्षणिक सहयोग का आह्वान किया।

भारतीय नौसेना का जहाज तरकश

सन्दर्भ

गिनी की खाड़ी में अपनी तैनाती जारी रखते हुए, भारतीय नौसेना का जहाज तरकश नाइजीरिया के पोर्ट लागोस पहुंचा।

प्रमुख बिंदु

• पोर्ट कॉल के दौरान, जहाज अंतरसंचालनीयता बढ़ाने और नौसेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए नाइजीरियाई नौसेना के साथ बातचीत करेगा।
• इसके अलावा, वह बंदरगाहों और सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लेगा।
• भारतीय डायस्पोरा और स्थानीय लोगों को अपने दल के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करने के लिए जहाज आगंतुकों के लिए भी खुला रहेगा।

MCQ, **Current Affairs**, **Daily Pre Pare**